



सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेश्वर
श्री स्वामी रामानंद
 दासजी महाराज
 श्री रामानंद दास अन्वेषक सेवा
 ट्रस्ट, तपोवन आश्रम

स्व. पं. पू. 1008 श्री रामानंद जी
 तपोवन मंदिर, तपोवन, सूरत

वर्ष-13 अंक: 38 ता. 03 अगस्त 2024, शनिवार, कार्यालय: 114, न्यू प्रियंका टाउनशिप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9085646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@surathbhumik.com /Surathbhumik.com /Surathbhumik /Surathbhumik /Surathbhumik /Surathbhumik

पहला कॉलम

हरिद्वार में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न

जिलाधिकारी एवं SSP ने प्रजापति मंदिर में किया जलामिषेक

हरिद्वार : (एजेंसी)

धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला आज सकुशल संपन्न हो गया है। जिसके बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्याल और एसएसपी हरिद्वार प्रमोद सिंह डेबवाल ने गंगा पूजन कर हथकी पौड़ी से गंगाजल लेकर हरिद्वार स्थित कनखल के दश प्रजापति मंदिर में जलामिषेक किया। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने पुलिस एवं प्रशासन का किया आभार व्यक्त

जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्याल ने कहा कि मेला सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने समन्वय से काम किया। धर्मनगरी में ये कांवड़ मेला सभी लोगों के सहयोग से विशेष कर पुलिस एवं प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय लोगों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से निर्विकल्पक हो गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 करोड़ 25 लाख कांवड़ियों इस बार कांवड़ मेले में आए और जल भरकर रक्नम हुए। उन्होंने आगे कहा कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है इसलिए वह गंगा पूजन एवं जलामिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने सभी शिव भक्त कावड़ियों के लिए मांगी से प्रार्थना करते हुए कहा कि सबको मनोकामना पूर्ण हो।

पुलिस कोर्ट में दिन रात किया काम-एएसएसपी

हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डेबवाल ने कहा कि मेला सकुशल संपन्न करवाने में पुलिस फोर्स ने दिन रात काम किया और 15 दिनों तक चले इस कांवड़ मेले में भारी भीड़ के बावजूद जाम की स्थिति नहीं पैदा होने दी। उन्होंने इसके लिए प्रशासन मुख्यालयी पुष्कर सिंह धामी एवं पुलिस के आला अधिकाधिकारी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा उन्हें पंचोत्सव पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी। वहीं एसएसपी ने मेला सकुशल संपन्न कराने में लगे सभी पुलिसकर्मियों एवं सामाजिक संस्थाओं, स्वस्थ विभाग एवं



प्रशासन का आभार व्यक्त किया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि यहां जल लेने आए सभी कांवड़ियों की मनोकामना पूर्ण हो।



वायनाड त्रासदी- राहुल गांधी का वादा, कांग्रेस परिवार 100 से ज्यादा घर बनाकर देगा

वायनाड। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को केरल के वायनाड के चूरलमाला, मेप्पाडी में जिला प्रशासन, नव अधिकारियों ने जानकारी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह कल से ही यहां हैं, हम घटनास्थल और क्षतिग्रस्त में गए थे, हमने यहां की स्थिति का आकलन किया। प्रशासन, पंचायत के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमें संभावित हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घर और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी मिली है। हम यहां हर संभव मदद करने के लिए हैं। कांग्रेस परिवार, यहां 100 से ज्यादा घर बनाने का वादा करना चाहता है। यह एक भयानक त्रासदी है, केरल ने एक क्षेत्र में इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है। राहुल ने कहा कि वह इसका कारण अलग तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। यह एक अलग स्तर की त्रासदी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को केरल के वायनाड पहुंचे थे। जहां हाल ही में भारी बारिश के कारण तैडस्ताइड आया था जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी कई लापता हैं।

हिमाचल में संकट का दौर.....आठ स्कूली बच्चे लापता

सनेग गांव के 34 लोग लापता

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। शिमला, कुलू और मंडी जैसे तीन इलाकों में बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई और हदसे में 50 लोग लापता हैं। अक्सर सनेग गांव के आठ स्कूली बच्चों के लापता होने की खबर है। लापता बच्चों में सात लड़कियां और एक लड़का शामिल है। लापता हुए सभी छात्र बेडमिंटन और वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद ने कहा कि लापता छात्रों में 12वीं ब्लास के हैं, 4 मैट्रिक और 6वीं और 9वीं कक्षा के एक-एक छात्र शामिल हैं। ये सभी छात्र स्थानीय निवासी थे। ये सभी बेडमिंटन और वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। प्राकृतिक आपदा से जुड़ा रहे हिमाचल में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.2 की रही। हालांकि, इसमें किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रामपुर के समेव गांव के 34 लोग लापता हैं, इसमें 18 महिलाएं शामिल हैं। वहीं, मंडी के रामनग वाग तक जाने वाले सभी पारसे क्षतिग्रस्त हैं। जामा जहाज झरने बंद रहे हैं। कम्बल-कीचड़ और चड़ने राहत और बचाव दलों को हर एक कदम पर चुनौती दे रहे हैं।

इंडी ने राशन गोदाले मामले में टीएमसी नेता से की 14 घंटे पूछताछ फिर किया गिरफ्तार

कोलकाता। इंडी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 पराना जिले के देगा से गुणमूल घोष के नेता को करोड़ों रुपए के राशन वितरण गोदाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि इंडी ने टीएमसी के देगा ब्लॉक अग्रह अनीस उर- रहमान और उनके बड़े भाई को गुनवार देर रात कोलकाता रिश्त कार्यालय में करिव 14 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि रहमान और उनके भाई को राशन वितरण सोदाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हे विकल्पिकीय जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। रहमान बंगाल के पूर्व वन मंत्री ज्योतिषिय मलिक के करीबी हैं। इंडी पूर्व मंत्री को गोदाले के सिलसिले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अधिकारी ने बताया कि इंडी अधिकाधिकारी ने चावल मिल मालिक और पूर्व मंत्री के एक अन्य करीबी बारिक विद्यास को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने बताया कि इंडी ने मंगलवार को बारिक विद्यास के आवास और चावल मिल पर छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और सुवर्ण अंकुश अमीरात में संग्रहित में निवेश के संबंध में कुछ दस्तावेज जवाब दिए थे।

राज्यपाल सम्मेलन: एक समृद्ध अनुभव होगा और कामकाज में मदद मिलेगी : राष्ट्रपति मुर्मू



नई दिल्ली। (एजेंसी)

दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुई दो दिनी राज्यपाल कॉन्फे स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपालों को संबोधित किया। सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सम्मेलन का विचार-विमर्श प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा और उन्हें अपने कामकाज में मदद मिलेगी। मुर्मू ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के विकास, युवा विकास, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

को लेकर हर राज्यपाल को पड़ोसी राज्य के साथ बैठक करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रदेश के राज्यपाल मुंबई पटेल ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों के साथ बैठक भी की है। बैठक में एमपी के सीमावर्ती जिलों और दूसरे राज्यों के एमपी से सटे सीमावर्ती जिलों की समस्याओं, बड़ी परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई थी। अब दिल्ली में हो रही राज्यपाल कॉन्फेस में इन मुद्दों पर केंद्र की ओर से रिपोर्ट ली जाएगी और अब राज्यपालों के दिल्ली प्रवास और दिल्ली में होने वाली बैठक के मद्देनजर राज्य सरकार ने संबन्धित विभागों को निर्देश जारी कर विभाग से संबन्धित अपडेट जानकारी राज्यपाल को सौंपी है।

इस दो दिनी कॉन्फेस के पहले 10 राज्यों के राज्यपाल बसने के अनुसार राज्यपालों की भूमिका में बदलाव समय के साथ हुआ है। इस कारण कॉन्फेस में राष्ट्रपति मुर्मू राज्यपालों को कुछ और जिम्मेदारी भरे काम सौंप रहे हैं।

मध्य पूर्व में बढ़त तनाव.....

एअर इंडिया ने रद्द की उड़ान

दिल्ली से तेल अवनी और तेलअवीव से दिल्ली उड़ान निलंबित

नई दिल्ली। (एजेंसी)

एअर इंडिया ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण इजरायल के तेल अवीव से आने-जाने वाली अवीव उड़ानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एयरलाइन ने कहा कि उड़ान संचालन 8 अगस्त तक निलंबित रहेगी।

कंपनी मुकेश बहादुर अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं... हमारे मेहमानों और यात्रकों दल को सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एअर इंडिया हर सप्ताह दिल्ली से तेल अवीव के लिए चार उड़ानें संचालित करती है। एअर इंडिया ने कहा कि उड़ानें पश्चिम तेल अवीव से 1 अगस्त को दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली अपनी उड़ानें और तेल अवीव से दिल्ली जाने वाली उड़ानें को रद्द किया है। बाद में वे तेल अवीव से हमारा चीफ इम्प्लान्ट इंडिया और इससे पहले लिबरलइज्म के तेल माइक्रो को हटाने के बाद इजरायल से दुनिया भर में अपने राजनीतिक मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच तनाव ने बायो देशों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है।

इस दो दिनी कॉन्फेस के पहले 10 राज्यों के राज्यपाल बसने के अनुसार राज्यपालों की भूमिका में बदलाव समय के साथ हुआ है। इस कारण कॉन्फेस में राष्ट्रपति मुर्मू राज्यपालों को कुछ और जिम्मेदारी भरे काम सौंप रहे हैं।

राज्यसभा में सदस्यों ने उठाया अपने-अपने क्षेत्रों की समस्या

नई दिल्ली। (एजेंसी)

राज्यसभा में सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश को आपदा सहायता राशि मुहैया कराने से लेकर 'गिग वर्कर' को शोषण को रोकने और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दिल्ली तक सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने का मुद्दा उठाकर कहा कि वहां इंधन की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त राशि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को पिछले वर्ष आपदा से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हुई।

सूखा कानूनों का फायदा मिलना चाहिए और इसके लिए नेशनल फेडरल बन्वाया जाना चाहिए।

बीजु जनाता दल के मंत्रीबुद्ध खान ने नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर को सीधी हवाई सेवा से जोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि वहां एक पर्यटन स्थल भी है, वह ओडिशा से भी लगता हुआ क्षेत्र है। इस विमान सेवा से ओडिशा के क्षेत्रों को भी लाभ होगा। भाजपा की सीता वल्लभ ने कहा कि गाजीपुर से पांच किलोमीटर की दूरी पर अंधक में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हवाई पट्टी है, जिस पर चार्टर्ड विमान उतरते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए व्यावसायिक उड़ान शुरू की जानी चाहिए। इससे आस पास के कई जिलों के लोगों को आगमन का सुगम साधन मिल सकेगा। अभी इन लोगों को उड़ान फाइने के लिए वारप्राप्ति या गोरखपुर जाना पड़ता है। कांग्रेस की जे जे माथेर ने केरल में रेल नेटवर्क बढ़ने की मांग करते हुए कहा कि बजट में राज्य के बड़े सड पर मूक्य रूप से बजट का बंधन किया गया है। उन्होंने कहा कि केरल में रेलवे की कुछ परियोजनाओं पर कार्य बहुत धीमे चल रहा है, इसमें तेजी लाई जानी चाहिए।

पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़-भूकंप सब सह गया, नया वाला पानी में बह गया?

नई दिल्ली। (एजेंसी)

शतवर्षीय के केंद्रीय मंदिर का निर्माण करवाया था। एक समय ऐसा भी आया, जिग के मंदिर पूरे 400 वर्षों तक बर्क के नीचे दबा रहने का खतरा नहीं था। लेकिन 1200 वर्षों के बाद भी ये मंदिर अपने मूल रूप में ही सुरक्षित है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में ककरता में हुगली नदी पर हावड़ा बिजु का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये हावड़ा बिजु अपने मूल रूप में सुरक्षित है। इसी तरह वर्ष 1920 में अंग्रेजों ने मुंबई शहर में सीटीन वॉइंट को मालाबार हिल्स से जोड़ने के लिए अरब सागर के साथ एक नदीबंद खड़ी की थी जिसके साथ मरीना ड्राइव का निर्माण किया था और ये दीवार भी आज 104 वर्षों के बाद पूरी तरह से सुरक्षित है जबकि मुम्बई की तालकवत लहरें हर दिन इस दीवार से टकराती हैं। मुंबई को जिस इमारत में बीएसएम का दफतर है, उस इमारत का निर्माण वर्ष 1893 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आज बीएसएम का दफतर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस बिल्डिंग में है और ये बिल्डिंग आज भी बारिश, तूफान, आंधी और कई भूकंप को सहने के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन इस दफतर में बैठकर बीएसएम के अधिकारी मूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कुछ वर्षों भी टिक नहीं पाता है। यही स्थिति दिल्ली के इंडिया गेट, लाल किला और आगरा के ताजमहल की हैं, जो तीन सदियों के बाद भी सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में हर साल नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 74 हजार करोड़ रुपये, दिल्ली में 11 हजार करोड़

रुपये, हरियाणा में साढ़े 18 हजार करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश में 5 हजार करोड़ रुपये, उत्तराखंड में 13 हजार करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश में 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बारिश में ही टूट जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कक्रोटे रोड की औसत उम्र 25 वर्ष होती है। लेकिन ऐसी ज्यादातर सड़कें 4 वर्षों में ही टूट जाती हैं। बताते हैं कि हमारे देश में और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर्फ है? आज हमारे देश में नई-नई सड़कें, एक्सप्रेस-वे, बिल्डिंग, एक्वियट और रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन वो एक बारिश में ही टूट तोड़ना शुरू कर देते हैं। पानी अंदर भर जाता है या छान लाने के लगते हैं

रुपये, हरियाणा में साढ़े 18 हजार करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश में 5 हजार करोड़ रुपये, उत्तराखंड में 13 हजार करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश में 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बारिश में ही टूट जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कक्रोटे रोड की औसत उम्र 25 वर्ष होती है। लेकिन ऐसी ज्यादातर सड़कें 4 वर्षों में ही टूट जाती हैं। बताते हैं कि हमारे देश में और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर्फ है? आज हमारे देश में नई-नई सड़कें, एक्सप्रेस-वे, बिल्डिंग, एक्वियट और रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन वो एक बारिश में ही टूट तोड़ना शुरू कर देते हैं। पानी अंदर भर जाता है या छान लाने के लगते हैं



और ये स्थिति भी तब है, जब हमारे देश में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारों 10 से 11 लाख करोड़ रुपये खर्च करती हैं। दिल्ली का हर व्यक्तिक सरकार को सालाना 80 हजार रुपये का टेक्स देता है। महाराष्ट्र में ढाढ़ लाख रुपये, मुंबई में सवा दो लाख रुपये, वेगलूर में डेढ़ लाख रुपये, अहमदाबाद में 70 हजार रुपये और चेन्नई में हर व्यक्तिक सरकार को सालाना 75 हजार रुपये का टेक्स देता है।

राहुल गांधी झूठ का नैरेटिव और झूठ की खेती करते हैं: केन्द्रीय मंत्री गिरिराज

नई दिल्ली। (एजेंसी)

इडी छापेमारी को लेकर किए गए राहुल गांधी के दावे पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ का नैरेटिव और झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हतोत्साहित हैं। इसलिए यह झूठी अफवाह फैल रहे हैं इससे बड़ा झूठ विषय का नेता आज तक नहीं बना है। राहुल गांधी अपनी जाति बताने के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के दावे के बाद अब इस मुद्दे पर सिवासत शुरू हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा है।

सांसद संजय राज ने कहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो सरकार उसके खिलाफ साजिश रचती है। हमें कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी पर हमले भी हो सकते हैं। विदेश में साजिश रची जा रही है। सरकार राहुल गांधी से डर रही है। निपटोरी नेताओं पर गुंडों की मदद से हमले किए जा सकते हैं। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को छापेमारी के बारे में जानकारी होगी। जब-जब सरकार डरती है, एजेंसी को आगे करती है। ये सरकार डरी हुई सरकार है। एजेंसी

के तहत डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के टवील के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टेंगोर ने एजेंसीओं के दुरुपयोग पर लोकसभा में चर्चा के लिए संसद में नोटिस भी दिया है। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडी संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इंडी के अंदरूनी लोगों ने उन्हें इसकी जानकारी दी है। एएस पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने

लिखा-जाहिर है, दू दिन बन को मेरा चक्रव्यूह भाषण परसेट नहीं आया। इंडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाह फेलाकर इंडी का इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। बरां दं कि 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं।



उन्होंने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है।



संश्लिष्ट समाचार

ईडी हुई बुलडोजर पर सवार

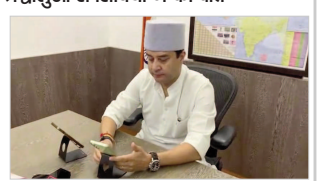
राज्य सरकार कुशावह की वैशकीमती जमीन जात अवैध निर्माण तोड़ने बुलडोजर लेकर पहुंची वी ईडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईडी ने बड़ा कारवाह करते हुए जौनपुर से समनखवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशावह की करोड़ों की मूल्य जात की ईडी के सामने पेश की है। सांसद बाबू सिंह कुशावह की ईडी टीम ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर भी हथार कर रखा था, जिसे देख लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। गौतमवाह है कि सपा सांसद कुशावह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) घोस्टले के आरोपी रहे हैं। घोस्टले के समय वे वृद्ध में परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर सरकार में खास निर्माणदायक निभा रहे थे। इस मामले में वे 4 साल जेल में रहे। जानकारी अनुसार, जौनपुर से समनखवादी पार्टी के सांसद और बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशावह की वैशकीमती जमीन पर ईडी ने कारवाह कर दी है। सांसद कुशावह को करोड़ों की जमीन लखनऊ के सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र स्थित स्कूल इंडिया के समीप है। चुकि सांसद कुशावह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएम घोस्टले के आरोपी रहे और ईडी टीम पीएमएलए मामले में जांच कर रही थी अतः इस कारवाह को उभारे जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम जांच-पड़ताल उभरते प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ स्थित करोड़ों की जमीन को जप्त करने का काम किया है।

बड़ी चालाकी से पीएमएलए कानून को मजबूत बनाया मोदी सरकार ने

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषणों के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रही है। राहुल ने कहा कि वे खुली बातों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है, 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अख्त नहीं लाता। इंडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना हो रही है। मैं ईडी का खुली बातों से इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से... इतना ही नहीं राहुल ने अपने पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारिक एएस हैडल को टैग भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के क्लॉक बताने है कि 2019 की बात है, जब राजस्थान में भाषण के फलस्वरूप नहीं था। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार ने पीएमएलए में बदलाव के लिए इस वन विधेयक को तैयार कर दिया था। दरअसल, पत्र विधेयक को राजस्थान में पेश नहीं करना पड़ता है। धन विधेयक को सौधे राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और बाहू बहसत से पास होने के बाद वह कानून बन जाता है। उस वक्त विपक्ष ने मामले पर बहुत हमला मचाया था। विपक्ष का कहना था कि पीएमएलए में मनी बिल जैसे कोई बिल नहीं है। जनकव्यूह पीएमएलए को मनी बिल के तहत लोकसभा से पारित कर दिया गया, ताकि केंद्र को सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इसका इस्तेमाल विधायी इस्तेमाल को साधने में करना चाहती है। अब वह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने भी संशोधन को सही ठहराया।

केदारनाथ में फसे शिवपुरी जिले के श्रद्धालुओं से सिंधिया ने की बात



शिवपुरी

शिवपुरी। केदारनाथ में आई प्रकृतिक आपदा के कारण शिवपुरी के शिवपुरी जिले के श्रद्धालु फस गए। कइयों को सुरक्षित निकालने के बाद शेष लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। वहीं केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरिंदर सिंधिया ने इन श्रद्धालुओं से बात कर उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सुबह केदारनाथ में बाढ़ल फल के कारण फसे हुए श्रद्धालुओं से बात की। उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र गुना-शिवपुरी के श्रद्धालुओं के सहाय के केदारनाथ में फसने की सूचना मिली थी। केन्द्रीय मंत्री ने इस सूचना पर एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यक्रम के माध्यम से बदरवाह के लोगों को जल्द नीचे लाने का आग्रह किया था। हालांकि, केन्द्रीय मंत्री लगातार जवाबदाह के मुख्यमंत्री से संपर्क में हैं, ताकि किसी शिवपुरी-बुन्दरवास वामी को जल में परेशानी न हो व जल्द सुबह निकाला जाए। बुन्दरवास की सुबह से फसे हुए लोगों का बचाव कार्य जारी है, उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीचे लाना जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने शुक्रवार को सुबह अपने अवास से सभी श्रद्धालुओं से वॉन पर बात की, नीचे सुरक्षित लाए गए श्रद्धालुओं से उनका हाल बात जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से बात कर कहा मैं वं चा, सभी को सुरक्षित लेकर नीचे आऊंगा, आप चिंता मत करना।

दादा पर ममता की मेहरबानी.....1 रुपये लीज पर 350 एकड़ जमीन



कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा मामला

कोलकाता। (एजेंसी) पश्चिम बंगाल में टीएम डंडिया के पुत्र कुचान और क्रिकेटर रहे सीएम गांगुली को जमीन देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में दखिलानेवाह याचिका में सीएम ममता बनर्जी सरकार के 350 एकड़ जमीन देने पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि ममता सरकार ने गांगुली को सिर्फ 1 रुपये की लीज पर 350 एकड़ जमीन पट्टे पर दी है। इस पीआईएल पर सुनवाई चिफ़फ़ंड मामलों के लिए गठित खंडीठ में होगी। ममता सरकार ने गांगुली को यह जमीन एक स्ट्रॉल फेक्टरी स्थापित करने के लिए दी है। जहालित याचिका में गांगुली को मालुमी जमीन में जमीन सौंपने के राज्य के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा

बीआरए विश्विद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में महज 12.43 प्रतिशत विद्यार्थी पास

मुजफ्फरपुर। (एजेंसी)

मुजफ्फरपुर की बीआरए विश्विद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में साल 2024 में मात्र 12.43 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। बता दें कि इस साल की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 3300 छात्रों ने परीक्षा दी थी जिसमें 1625 ने परीक्षा दी थी। इसमें से महज 202 ही पास कर सके हैं। सबसे ज्यादा कॉमर्स विषय में 32 परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुलमिति ने कहा कि पीएचडी परीक्षा पर तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट अब सभी विभागाध्यक्षों को भेजा जाएगा। विद्यार्थी को और से अपेक्षा लिखित परीक्षा का नंबर जारी नहीं किया जा रहा है। छात्रों के इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में नंबर का पता चलेगा। पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू

की प्रक्रिया अगस्त में होगी। इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए सभी विभागाध्यक्ष तैयार हैं। पीएचडी में सीटों की इंटरव्यू के बाद ही तय होगी, इंटरव्यू 20 नंबर का होगा। पीट का फाइनल रिजल्ट लिखित, इंटरव्यू और एंकेडमिक के प्लांट के आधार पर तैयार होगा। कुलमिति ने बताया कि पीट 2022 के अंतिम रिजल्ट के बाद पीट 2023 के लिए भी एक बार पोर्टल खोला जाएगा। कुलमिति ने बताया कि पीट 2023 की परीक्षा अक्टूबर में होने की उम्मीद है। अब तक करीब 2200 आवेदन आ चुके हैं। पीएचडी 2023 के लिए बिहार विवि पहले ही सीटें जारी करगी।

सरमा का राहुल गांधी पर तंज, सबकी पूछते हैं.....उनकी जाति पूछने पर नाराज

सोरेन सरकार बांगलादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही रवी। (एजेंसी) असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अजीब चीजें कर रहे हैं। वे एक और जगह-जगह पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं और जब लोगों ने उनकी जाति पूछ ली, तब वे सवाल उठाते हैं कि मेरी जाति क्यां पछे? आखिर अगर राहुल गांधी जातीय

जनगणना करना चाहते हैं तब बिना जाति पूछे यह कैसे संभव होगा? सरमा ने कहा, राहुल गांधी अजीब चीजें कर रहे हैं, क्या बोलते हैं...हलुत हो दिक्कत वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास बीबीडी है, जिसमें राहुल गांधी का नाम मुझालय में एक पत्रकार से उनकी और उसके मालिक की जाति पूछ रहे हैं। इतना उत्तर प्रदेश में भी एक पत्रकार से पूछ कि तुम ओबीसी हो क्या? उन्होंने जाति के सवाल इस तरह से पूछे थे कि लोग उन्हें मानने के लिए तैयार हो गए थे। सरमा ने कहा कि राहुल गांधी को सामनवादी

सोच है कि सबकी जातीय जनगणना हो, लेकिन खुद उनसे उनकी जाति नहीं पूछे जाए। वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, हिमंता बिस्वा सरमा, अनुपम बज्जुर और अमित शाह अपनी जाति बताएं लेकिन मैं अपने नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे नाम के आगे गांधी लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? सरमा झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं। वे दो दिनों के झारखंड दौर पर हैं। उन्होंने छात्रों से मुलाकात के बाद आरोप लगाया था कि झारखंड में झामुमो-कांग्रेस-जनद की गठबंधन सरकार बाज्जुरादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है।

क्या नई शिक्षा नीति में बिना प्राध्यापकों के पढ़ाई होती है सांसद सैलजा

कॉलेजों में प्राध्यापक नहीं, छात्रों के भविष्य से सरकार कर रही खिलवाड़

सिरसा। सांसद सुमीत्री सैलजा ने कहा कि कॉलेजों का नया सत्र शुरू हो चुका है लेकिन कॉलेजों में प्राध्यापक तक नहीं है ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे होगी उस पर कड़ा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण कार्य होता है। सैलजा ने कहा कि क्या नई शिक्षा नीति में बिना प्राध्यापकों के पढ़ाई होती है। सरकार हर बार झूठ बोलती है, पंजाब हरियाणा हरियाणा के तहत सरकार को निदेश दे चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रवेश परीक्षा में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का मन बना लिया है। मीडिया को जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि प्रवेश परीक्षा शिक्षा खासकर महिला शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से की कई घोषणाएं की गई हैं जो हवा-हवाई साबित हो रही हैं। सरकार बार बार घोषणा करती है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर बिल कोसिलोमीटर पर एक महिला महाविद्यालय खोला जाएगा पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आज भी महिला कॉलेज खोलने के लिए लागू मांग कर रहे हैं

लेकिन सरकार बहाना बनाकर उसे टाल देती है। जहां लोगों ने ज्यादा शोर मचाया तो वहां पर एक या दो कॉलेजों की कोटिंग शुरू करवा दिया। अब वहां पर विद्यार्थी कहां पर बैठेंगे और प्राध्यापक कहां। यह भी एक समस्या है। अभी तक तो सरकार ने कॉलेज खोलने के लिए भूमि तक का सपना नहीं किया है। प्रदेश में प्राध्यापकों की कमी है, सरकार भती को लेकर गंभीर भी नहीं है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र देकर कब्जाल किया है कि राज्य में 4738 प्राध्यापकों के पद जो कुल पदों का 60 फीसदी है, रिक्त हैं। इसका उल्लेख उच्चकोर्ट को 21168/2021 के फैसले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 20 सितंबर 2023 को दिया था में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में अंतिम 22/2024 को रिजल्ट 24619 के प्लाट नंबर 13 में सफाई लिखा है कि सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया है वह अयोग्य है।

मध्यप्रदेश की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को धौलपुर में 650 करोड़ का काम

विधानसभा में उठा था मामला, मंत्री ने दिया जांच का भरोसा

धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले में कांटेनर सिविल लिस्टेड परियोजना का टेंडर लेने वाले कंपनी को सौंपने का मामला उठाया गया था। मंत्री ने जांच का भरोसा दिया। उन्होंने जानना चाहा कि धौलपुर में जीपीओआर को कौन से कार्य किस दर पर दिया गया। क्योंकि टेंडर लेने वाली फर्मों में एक मध्य प्रदेश की है जो वहां पर ब्लैक लिस्टेड है। जबकि इस जिले में 650 करोड़ का टेंडर दिया गया है। इस सवाल पर जल संसाधन मंत्री राठौर ने बताया कि निम्नानुसार टेंडर लेने वाले सेवेक से इस तरह की सभी शौं को लेकर शपथ पत्र लिया जाता है। अगर मैंमें सौंप जीपीओआर लिस्टेड-कू-पा कारपोरेशन (जिआईएल) द्वारा तथ्यों को डिक्लर एस कोड शपथ

पत्र दिया गया है, तब उसकी जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारियों एवं टेंडरमंट फर्म के खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके फल में जल संसाधन विभाग की प्रवेश में जल संसाधन विभाग को उसकी योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार 4854.36 करोड़ रुपए का बजट अंश वरिष्ठ हुआ था। विभाग द्वारा परियोजनाओं की जीपीओआर तैयार कर प्रशासनिक एवं किं तीय-2 वीकलित जारी की जाती है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि सौंपने-बहाव-एक वर्ष से अधिक होती है, जिससे बजट की मांग वर्षवार, अनुमानित की जाती है तथा परियोजना पर कार्य करवाए जाने के लिए निविदा/निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

कारें चुराने वाला गिरोह पकड़ाया, डीसीपी के सामने दिया कार चुराने का डेमा

चार मिनट में लग्जरी कार को किया स्टार्ट, अब तक चुरा चुके हैं 100 ज्यादा कारें नोएडा। (एजेंसी) चार मिनट में लग्जरी कार को चुरा चुके हैं। चोरों ने पुलिस से सामने करके पर चार मिनट का कार चुरा का डेमा दिया कि कैसे लग्जरी कारों का गेट खोलकर चार मिनट में उठे लेकर फरुकवाह हो जाते हैं। निरोह लज्जरी कारें चुराकर महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में 50 और 40 फीसदी कम दामों में बेचे थे। ग्राहक को फजी आसरी देते थे। इनके पास से 17 लज्जरी कारें बरामद हुईं, जिसे वे बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया

कि सीआरटी और थाना सेक्टर-24 पुलिस ने गिरोह के पांच लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए एक बदमाशों ने महज चार मिनट में डीसीपी फ्राइम के सामने एक लज्जरी कार को स्टार्ट कर दिखाया। चोर ने पहले कार का शीशा तोड़ा। उसके पैसे खोला। इसके बाद की-प्रोग्रामिंग डिज के जरिए कार के इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में नजमेट को रि-प्रोग्राम किया। बाइपास से कनेक्ट करके पेशर वायु और नया की-होड जनरेट करके कार स्टार्ट की। डीसीपी ने

बताया कि अगर प्रोग्रामिंग फेल हो जाए तो वे नराली चम्बी और अन्य तरीकों से लॉक तोड़ेंगे। लज्जरी कारों की चोरों के बाद गिरोह 10 से 15 लाख में और सामान्य कारों को तीन से पांच लाख रुपय में बेच देता है। जिन गिरोहों को बाँध कर पकड़ा कर पाते थे, उनके पुरजे निकालकर बेच देते थे। बेचने के बाद मिली रकम से मौज मस्ती

करते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अन्वय अरुं डीएम, गैजेट मॉडर्न, आसिफ उर्फ पाट, अंडरमोड रज्जक के रूप में हुई है। ये पहले भी जेल जा चुके हैं।

अब वायनाड त्रासदी पर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दे सकेंगे अपनी राय

सीएम विजयन ने विवादपर अदरेश वापस लेना का लिया फैसला

वायनाड। केरल सीएम पिनारय विजयन ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के उस विवादपर अदरेश को वापस लेने को कहा है, जिसमें वैज्ञानिकों को वायनाड में हुए भूस्खलन पर अपनी राय और अध्ययन रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश करने को कहा गया था। साथ ही सरकार ने वैज्ञानिकों को भूस्खलन क्षेत्र का दौरा करने से भी मना किया था। पिनारय विजयन ने कहा कि मुख्य सचिव को तुरंत हस्तक्षेप करने और कि मुख्य सचिव को इसे वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे गलतफहमी स्पष्ट हुई है। राज्य के मुख्य सचिव को पीछे फेरवृक पाट्ट में लिखा-इस निर्णय के पीछे वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़े लोगों को हतोत्साहित करना नहीं है। मौसम में होने वाले बदलावों और मौजूद परिस्थितियों के बारे में जानकारी सुटाने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत होती है। लेकिन, इस समय सरकार का पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर है। राज्य सरकार के बयानों का जवाब नहीं देना न निराशा जगाए। एक अधिकारी ने कहा कि त्नािनक अध्ययनों का बहुत महत्व है जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राहत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन वह तब तक अदरेश है कि बयानों या राय की गलत व्याख्या के कारण व्यापक चर्चावह और सच को भ्रष्ट करने का डौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को भूस्खलन क्षेत्र का दौरा करने से भी मना किया था। पिनारय विजयन ने कहा कि मुख्य सचिव को तुरंत हस्तक्षेप करने और कि मुख्य सचिव को इसे वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे गलतफहमी स्पष्ट हुई है। राज्य के मुख्य सचिव को पीछे फेरवृक पाट्ट में लिखा-इस निर्णय के पीछे वैज्ञानिक संस्थानों से जुड़े लोगों को हतोत्साहित करना

संपादकीय

कुछ से केरल तक

भारत का मौसम की मार से प्रभावित और खिलित होना स्वाभाविक है। उत्तर भारत में कुछ से लेकर दक्षिण के केरल तक अर्ध जलवायु मंजर सामने आए हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत के कुछ बड़े इलाके में बुधवार को जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, उससे पिता का ज्यादा स्वाभाविक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इतने ही समय में देश के सात राज्यों में 32 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं। जिस तरह हिमालय में पहास से ज्यादा लोग लापता हैं, दस से ज्यादा की मौत हो गई है, उससे भी त्रासद स्थिति केरल के वायनाड में बनी हुई है। बारिश और भूकंपन से मरने वालों की संख्या बह 300 का आंकड़ा पूरे वाली है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग दब लापता हैं। क्या इन मौतों से बचा जा सकता था? यह बहस का विषय है और कोई भी इस त्रासदी या किसी तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी नहीं लेगा। केन्द्र सरकार और केरल सरकार के बीच जो दुखद आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं, उनसे आम बहने की जरूरत है। यह समय सातवां और सुधार का है। दरअसल, भारत में मौसम को समझना में समाज और उसके अनुकूल व्यवहार को ही जरूरत है। कभी खूब गीम, सूखा, तो कभी खूब बारिश, यहां ऐसे विरोधाभास को सहन ही स्वीकार करना चाहिए? मौसम की विचित्रता बढ़ती चली जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को बताया कि रात के तापमान के मामले में भारत में सबसे गर्म जुलाई माह का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। औसत तापमान में भीती जुलाई 1901 के बाद दूसरी सबसे गर्म जुलाई रही है, जबकि देश के कुछ हिस्सों में असाधारण वर्षा हुई है। जुलाई के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, तो बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में जुलाई महीने में 20 से 59 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज हुई है। पूर्वोत्तर में भी सिक्किम और मेघालय को छेड़ दीजिए, तो बाकी जगह कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में क्रमशः सामान्य बारिश रही है। जुलाई के महीने में केरल गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की रही है, जहां सूखे वर्षा हुई है। बिहार और झारखंड के अनेक खानों को खेतों के सूखने की चिंता है। नान के पौधों की पानी बढ़ाएं, अगर पानी न बरसा, तो उपज पर असर पड़ जाएगा। यही कामना रहती है कि आसपास के अनुकूल बारिश हो, पर ऐसा होना कहां है? अब एक बड़ा सवाल यह है कि अंतर केला बीतना? मौसम विभाग की माने, तो अगस्त में देश में मासिक वर्षा 94 प्रतिशत से 106 प्रतिशत के बीच सामान्य सीमा में रहने की संभावना है। हालांकि, कहीं बहुत ज्यादा, तो कहीं बहुत कम बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां सबसे बड़ी चिंता यह है कि वर्षा जलित हालात को जानबूझकर नष्ट से कैसे रोका जाए? सामान्य शहरों में बेसमेंट या भूगत बनी रहे, पर भारी बारिश के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सूखे चौड़ी और समतल सड़कें बन रही हैं, पर अत्यधिक जलवायु की स्थिति में क्या किया जाएगा, इसकी तैयारी शासक किसी भी शहर में सोचें अना मुहूर्त सुविधा है। बिजली के बेतरतीब तार और अन्य प्रकार की शहरी सुविधा भी सुरक्षित का कारण बनने लगी है। यह समय है, जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अपनी कमियां से सीखकर देश के सामने एक आदर्श पेश करना चाहिए।

आज का राशीफल

- मेघ** व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उदर निकाय या लघु का रोग से पीड़ित रहने। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है।
- वृषभ** व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग या सौजन्य मिलेगा। यात्रा देखावट को स्थिति सुदृढ़ व सावधान्य होगा। स्वयं पैसे के लोभ देन में सावधानी अपेक्षित है।
- मिथुन** जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रक्षा इच्छा कार्य सम्पन्न होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। पत्नी या पति परिवर्तन में सुकृष्ट मिलेगी। व्यर्थ को लागू न करें।
- कर्क** आर्थिक दृष्टि से लाभवृद्धि होगी। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। स्वभावानुरूप की लाभ मिल सकता है। शिक्षा प्रतिभोगिता के क्षेत्र में आशावादी प्रभाव मिलेगा। दायमत्व जीवन सुखमय होगा।
- सिंह** व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक सुखद हो सकता है। नई नौकरी या नवीन जगह का सुख मिल सकता है। शासन सेवा का सहयोग मिलेगा। प्रथम प्रयास प्रभावी होगा। भाग्यवत् सुखद समाचार मिलेगा।
- कन्या** आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आशावादी चरित्रों में वृद्धि होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पिता या उच्चधिकारी का सहयोग मिलेगा।
- तूला** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संबंधित अधिकारी या पद के मुखिया का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा देखावट को स्थिति सुदृढ़ व सावधान्य होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भावनाएं छोड़ें।
- वृश्चिक** जीवनसाथी का सहयोग या सौजन्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रक्षा इच्छा कार्य सम्पन्न होगा। अनजानी यात्रा करनी पड़े सकती है। किसी सफर में सुकृष्ट मिलेगी। किसी बहुमुल्य वस्तु के पाने की अपेक्षा पूर्ण होगी।
- धनु** राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धन में अपने सामान के प्रति सचेत रहें। खरीद या खाने को आशंका है। नैतिक निकाय के खतरे में सावधानी रखें। दूरदर्शन से सहयोग लेने में सफल होंगे। मैत्री संबंध प्रभावी होंगे। मन स्वस्थ होगा।
- मकर** व्यावसायिक योजना सम्पन्न होगी। नौसे रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। वाद विवाद को स्थिति सहकरणी होगी। स्वास्थ्य पक्ष में सुधार होगा। भाग्यवत् सुखद पेशा होगा। शिक्षा आर्थिक लाभ मिलेगा।
- कुम्भ** आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आशावादी चरित्र से आदर्श शक्ति सम्पन्न देना व सफल देना। किसी तरह के खतरे या खोरी होने की आशंका है। दूरदर्शन से सहयोग लेने में सफल होंगे। मैत्री संबंध प्रभावी होंगे। मन स्वस्थ होगा।
- मीन** आर्थिक योजना फलीफूल होगी। उद्यम पर सफलता का लाभ मिलेगा। स्वयं पैसे के लोभ-देन में सावधानी अपेक्षित है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। निजी सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुखमय में वृद्धि होगी।

विचारमंच

(लेखक- सतत नेन)

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला 6-1 से सामने आया है। छह जजों की खंडपीठ ने कहा है, आरक्षण को यह है संविधान के आधार पर जातियों के आधार पर कटा तब फिर जाने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग में अभी 8 लाख आर्थिक को आधार सीमा लागू है। परंपरा और परंपरा वर्ग के आरक्षण में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, जातियों के अंदर उपजातियों की कैटेगरी बनाने में संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का कोई उल्लंघन नहीं होता है। जिन परिवारों और जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हक नहीं मिलना चाहिए। सभी वर्ग के आरक्षण में यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। केन्द्र एवं राज्य सरकारों को आय की सीमा को आधार बनाकर आरक्षण लाभ देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ और मज्जा से सब केंद्रीय नहीं बना सकती हैं। यदि ऐसा करती हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा समय-समय पर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिए गए अपने फैसले को बल दिया है। जिसमें कहा गया था, राज्य सरकार आरक्षण कोटे में सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश से अब राज्य सरकारें परंपरा, परंपरा कोटे में पिछड़े वर्ग के आधार पर सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की देशभर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। बिहार की लोपना ने इसका विरोध करते हुए पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को सुप्रीम कोर्ट की सर्वगत काराकर आरक्षण व्यवस्था का सुनिश्चय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्यों को अब वह अधिकार मिल गया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करे, सरकार

की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ और मज्जा से सब केंद्रीय नहीं बना सकती हैं। यदि ऐसा करती हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा समय-समय पर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिए गए अपने फैसले को बल दिया है। जिसमें कहा गया था, राज्य सरकार आरक्षण कोटे में सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश से अब राज्य सरकारें परंपरा, परंपरा कोटे में पिछड़े वर्ग के आधार पर सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की देशभर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। बिहार की लोपना ने इसका विरोध करते हुए पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को सुप्रीम कोर्ट की सर्वगत काराकर आरक्षण व्यवस्था का सुनिश्चय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्यों को अब वह अधिकार मिल गया

है। वह आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण लागू कर सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब राज्यों के ऊपर है। वह जल्द से जल्द आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण को लागू करे। राज्य की जायें आर्थिक आधार के लाभ से भी लोपना विसर्जित हैं। उन्हें आरक्षण दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्यों को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रही है। सात सरकारी की बचने में आदेश दिया है। उनके बाद नई आरक्षण व्यवस्था में सभी वर्गों को इस्का लाभ सभी वर्ग को हासिल हो। इसके लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। रहलें गांधी और इंदिरा गणधन के दल के सरकार से जाति आधारित जगणना की मांग कर रहे हैं। 2021 की जगणना पिछले 4 वर्षों से लंबित है। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्र सरकार जगणना करते समय इनकी तन विधियों पर जगणना कराएगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर परंपरा परंपरा को पिछड़े वर्ग के साथ-साथ

सामान्य वर्ग की भी जानकारी सामने आ जाएगी। केन्द्र एवं राज्य सरकारें इन आंकड़ों के आधार पर योजना बना सकेंगी। केन्द्र सरकार जाति आधारित जगणना करने के लिए विषय की मांग पर अभी सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार पर अब केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है। एक आदेश यह भी व्यक्त की जा रही है, केन्द्र सरकार जाति जगणना करने के विकल्प में सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यों को अधिकार दिया कि वह सर्वे के माध्यम से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर उदात्त करके, आरक्षण को लेकर जो बवाल सारे देश में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राजनीतिक दलों में भी सहमति बनना संभव हो गया है। 1985 के बाद जब संघ मंचिदर आंदोलन शुरू हुआ। उसके जवाब में मंडल कमीशन को सामने लाया गया। जाटों के राजनीति में कांग्रेस अलग-अलग पड़ गई थी। जिसका फायदा 1989 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी

अर्थ क्षेत्रीय दलों को पिछले 30 वर्षों में राजनीतिक रूप में मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है। यदि यह ठीक भावना के साथ लागू कर दिया जाता है। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था विभिन्न वर्गों में लागू की जा सकती है। अज्ञानों वॉल से दूरे-दूरवारी और गुलामी के शिकार पिछड़े वर्ग, परंपरा, परंपरा के साथ-साथ सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी सरकारें याद द सकती हैं। जो उन्हे संविधान के अनुच्छेद 14 और 341 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो समाज के सभी वर्ग को इसका लाभ शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक पाश्चात्तिका से मिल सकता है। आरक्षण नियमों में पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी। आरक्षण का लाभ एक बार मिलना है। यह सब पीढ़ियां तक मिलाता रहेगा। इस विवाद का भी समाधान करने का मोसा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मिल गया है।

अग्निपथ योजना में सुधार की काफी गुंजाइश

मनोज जोशी

पिछले शुक्रवार द्रास में आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर अभिनय युद्ध का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा इस योजना का उद्देश्य वरनों को युवा बनाए रखना है जे एक ऐसी सेना जो युद्ध के लिए निरंतर चुस्त रहे। उन्होंने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे को राजनीति का विषय बना दिया है। उन्होंने इससे भी कड़े शब्द बरते, लेकिन सवाल है कि यह सब कहने के लिए क्या यह अवसर उचित था? आदर्श रूप में, इस पवित्र दिन को मनाने के लिए मंच पर विपक्ष और प्रधानमंत्री, दोनों को एक साथ होना चाहिए था। परंतु यह अपेक्षा शायद कुछ ज्यादा ही हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 सालों में सेना के स्वरूप में काफी सुधार किया गया है। वीक ऑफ डिफेंस स्ट्राफ (सीडीएस) को नियुक्ति, सैन्य मामलों के लिए अलग विभाग का गठन, सुधरे रूप में सैन्य खरीद नीति, रक्षा उद्योग को स्वदेशीय तकनीक विकसित करने की बाधाता, रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी को अनुमति और इन्हें 32% अनुसंधान एवं विकास राशि का 25 फीसदी बढ़िया करवाना जैसे अनेक उपाय किए गए हैं। लेकिन सेना को लेकर अभिनय योजना अपने आप में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी है। इस योजना के तहत एक युवा की सेना में भर्ती 17-21 साल के बीच होती है, उसका सेवाकाल चार साल का होगा और सेवावृत्ति उपरांत एकमुश्त रकम मिलनी है। चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अभिनयी में से 25 प्रतिशत को सेना में आगे 15 साल या अधिक कार्यकाल की श्रेणिका होगी। लेकिन बाकी बचे 75 फीसदी के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी का विकल्प हो सकता है, जहां भर्ती में उन्हें तरजीह मिलेगी। इस योजना पर विवाद उस तब उठ खड़ा हुआ जब पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम ने विमोचन के लिए लॉकअप किया था। उसी वक यह योजना नौसेना और वायुसेना के लिए 'बिन बायोनो की बिजली गिरना' बनकर आई और खुद उन्होंने जो प्रारूप सरकार को सौंपा था, वह केवल थल सेना के लिए था और उसमें भी 75 प्रतिशत अभिनयी को फोर्जन में आगे बंधे रहना था, केवल शेष 25 फीसदी को सेवायुक्त करना था। परंतु रक्षा मंत्रालय ने इसको एकदम उलटा कर दिया, यानी 75 प्रतिशत अभिनयी को कार्यवृत्ति और 25 फीसदी को सेना में बनाए रखने वाला प्रावधान बना डाला। राजनीति की वहल से, आरंभ से ही अभिनय योजना को लेकर विवाद होने लगे थे और दोनों पक्षों ने इस पर खेत किया, मुख्य सवाल तो अक्सर किया जाता है: हम अभिनयी के लिए अधिक क्या कर सकते हैं? फिर हमारे पास उस अन्य प्रश्न का भी ठोस उत्तर नहीं है कि अभिनयी सेना के लिए क्या और कितने उपयोगी होंगे? इस बाबत मुख्य दलील यह दी जाती है कि अभिनय योजना



सेना के जवान की औसत आयु बनिस्वत युवा बनी रहेगी। सरकार की ओर से दिए शपथपत्र में दावा किया गया है कि अफसर पद से नीचे, भारतीय सैनिक की औसत आयु विषय में सबसे अधिक, 32 साल है, जबकि वैश्विक औसत 26 वर्ष है। लेकिन दशकों से सेना में भर्ती की उम्र सदा 16.5 से 21 वर्ष के बीच रही है। कुल 75 प्रतिशत अभिनयीओं को सेवावृत्ति और प्रत्येक भर्ती वक में नई उम्र के युवाओं की औसत बनाने से योजनाकारों को उम्मीद है कि इससे फौज की औसत आयु कम हो पाएगी। किंतु जैसा कि पहले कहा, बदले में प्राप्ति क्या होगी? भारतीय सेना में भर्ती की कुछ हकीकतें हैं। देखा गया है कि जो युवा जल्दी भर्ती होते हैं, अक्सर उनका भार और पहिचान स्तर उनकी प्रष्टुभूमि में विविधता के हिसाब से कम होता है। पहले ही महीने का प्राथमिक प्रशिक्षण चरण हुआ करता था, उसमें शुरुआत नए सिर से करनी पड़ती थी, जिसमें यह वक उसे शारीरिक रूप से तार्ना करने और अनुशासन में दातने में निकल जाता था। इसके बाद शुरु होती व्यावसायिक प्रशिक्षण, चाहे उसे अग्रिम दरते का फौजी बनाना हो या अधिक तकनीकी हुनरपुत्र जवान, मरलन, टैक, तोप, वायु रक्षा प्रणाली चलाने वाला। इनमें मामूली योग्यता पाने के लिए भी एक और साल खपता है। जबकि अब महान छह महीने के प्रशिक्षण के बाद अभिनयी को सेना में भर्ती किया जा रहा है। रंगरुट की प्रामाण्य प्रष्टुभूमि, शिखा का स्तर और किसी उम्र में भर्ती हुई, इनके परिश्रम में लगता है कि अभिनयी कोई बहुत बंदिया कोशल विकसित कर पाएंगे। जो देश हम से आगे है, वह नया रंगरुट पहले से किसी न किसी कोशल से युक्त होता है जैसे कि वाहन चलाने का हुनर, लेकिन भारत में इसके लिए भी तैनी महीने तक लग सकते हैं। पूर्व प्रष्टुभूमिल अरुण प्रकाश का कहना है, कदाचित अभिनयी थल सेना के लिए उपयोगी हों, जहां आक्रमण में अग्रिम दरते का फौजी बनने के लिए अधिक तकनीकी योग्यता की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वायु सेना और नौसेना के लिए यह बड़ी समस्या बन जाएगी, जहां किसी नए

भर्ती युवा को समुचित कार्यकारी अनुभव पाने के लिए कम से कम 5-6 साल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही उसे किसी अतिरिक्त का हिस्सा या खतरनाक अस्त्रों का रख-रखाव, अतिरिक्त मशीनी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने का काम सौंपा जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मनेरथ केवल फौज की औसत आयु कम करना है न कि कोई अन्य उद्देश्य। लेकिन यदि पिछली बातों को याद करें तो सरकार के लिए इस तथ्य को मानने की जरूरत है कि यह योजना केवल तैयारी पक्ष कम करने की जाई से है, जिसका लाभ वैसे भी एक दशक बाद होना शुरू होगा। फिनाल सेनावृत्ति फौजियों को पेशाने देने में कुल खर्च 11.4 लाख करोड़ रुपये आता है अर्थात् कुल खर्च का 22.7 फीसदी, जिसे सेना के गले में बंधे भारी पथवर की तरह लिया जाता है। विगत में युवा सेवा बल बनाने की मांगों के चलते जकरनी नहीं कि फायदे के बदले युवासेना करावें। इस योजना को बंद करने की बजाय सरकार इसमें बदलाव लाए और खामियों को दूर करे, मसलन, प्रशिक्षण और कोशल विकास के विषय में। अभिनयी का कार्यकाल चार साल से बढ़ाकर सात वर्ष करने का सुझाव अरुण हो सकता है, और पिछले कुछ समय से इसकी मांग हो रही है। इससे प्रशिक्षण के लिए समुचित वक्त मिल पाएगा और ऐसा फौजी सेवा बल को प्रभावशाली योगदान भी दे पाएगा। इस नए प्रावधान के मुताबिक जब तक कोई अभिनयी सेनायुक्त होगा तब उसकी उम्र 24-28 साल के बीच होगी, जो नौकरी के विभिन्न मौकों के लिए आदर्श होगी, कुछ वक लगेगा पर ऐसे अक्सर उनके लिए बनने वाले होंगे। और यह सनर रहे, कारगिल युद्ध-1999 में 550 से अधिक को फौजी शहीद हुए थे, व सभी पूरी तरह प्रशिक्षित, तपकर निकले और प्रतिबद्ध सैनिक थे न कि अभिनयी। अभिनय योजना का इस किस्म का इम्तिहान होना बाकी है। लेखक अंजितर रिसर्व फौडरेशन में प्रतिष्ठित अध्येता हैं।

तो अब अदालत को भी पलटने का हक

(लेखक राकेश अवल)

7 आरक्षण के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को लेकर नाना-प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग और राजनीतिक दल इस फैसले से खुश हैं तो कुछ नाराज, क्योंकि अदालत ने अपने डेढ़ सप्ताह पुराने फैसले को पलटते हुए कोर्ट के भीतर आरक्षण कोटे तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। शीर्ष अदालत का फैसला जहां आरक्षण विरोधी संघ, भाजपा और अन्य दलों के एजेंडों पर कुतरावण है वहीं कुछ दलों के लिए राजनीति चमकने का अवसर भी। हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। आजादी के बाद से ही ये देश आरक्षण और जातियों के बीच झूल रहा है या कठिने पिस रहा है। कुछ लोग और चर्चा चाहते हैं कि अब देश में जाति और जातिगत आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाये क्योंकि ये दोनों ही बराबरी और विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि जब तक समाज में आर्थिक बराबरी न आ जाये तब तक जाति को तो पता नहीं किन्तु आरक्षण को बनाये रहना चाहिए [जाती को लेकर हमारे समाज की मान्यता भी भिन्न है। कोई कहता है कि जाति न पुणे साथी की पुष्ट लीजिये, तो कोई कहता है जाति-पात पूरे नहीं को,हरि को भजे सो हरि को होवा। इसके बाद ही हमारी संसद में आज भी जाति पुष्टि जाती है और निर्ममता से पुष्टि जाती है।] बात एकदम ताजा है। शीर्ष अदालत [सुप्रीम कोर्ट] ने 2004 के डेढ़ विरोधा केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा

कि राज्यों को अना-अजना कैटेगरी में संवैधानिकरण का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अग्र्याम प्रतिनिधित्व है। जस्टिस पी. आर. गवई संमत कर जजों ने यह भी कहा कि अना-अजना कैटेगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मंत्रीमंत्र समर्थ में क्रीमीलेयर का सिद्धांत रिफ ऑबिसेरी में लागू है तब तक जजों की बचने के 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस वेता पण, त्रिवेदी का फैसला अलग था। अब सवाल ये है कि क्या नेताओं की तरह अदालत भी अपने फैसले समायुक्त बदल सकती है? ये ररे दिहास से बिलकुल बंदत सकती हैं। वयोंकि फैसले व्यक्तिक करते हैं मशीनी नहीं। यदि शीर्ष अदालतों में फैसले मशीनी करती तो मुश्किल कि विे आपन ही फैसले न बदलतीं लेकिन जब व्यक्तिक फैसले करते हैं तो उन्हें फैसेट बदलने का हक है। वयोंकि कोर्ट भी फैसला समीक्षा के योग्य होता है और सो फीसदी सही नहीं होता। उसमें सरोधान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अर्थात् फैसेट बदलने का हक केवल इतने दश है। व जगणनासे के न्यायिक के अनुभव चलती है। कानून और सामंथा तथा तर्क-वितर्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं। यदि कौटिल्य के यही मान्यता जब पहले शीर्ष अदालत में आया था तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को संवैधानिकरण के शान कोर्ट की इजाजत नहीं है लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट के छह जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि, जस्टिस वेता त्रिवेदी ने छह जजों से असहमति जताई।

वीफ जस्टिस की अगुआई वाली सात जजों की बचने के हक है कि अनुसुचित जाति के संवैधानिककरण से संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इससे अनुच्छेद-341 (2) का भी उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद-15 और 16 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यों की रिजर्वेशन के लिए जाति में संवैधानिककरण से रोका है। सुप्रीम कोर्ट जाति शीर्ष अदालत शीर्ष ही होती है। वो बहुत सोच-विचार के बाद बहुमत से फैसले करती है। सुप्रीम कोर्ट में बहुमत चलने के अतिरिक्त नहीं। सभ्यता के साथ ही असहमति का भी सम्मान किया जाता है। भले ही असहमति को सभ्यता के आगे नमस्कार होना पड़ता है। फैसेट करने का ये लोकतंत्र यदि हमारी संसद में भी हो तो न कोई किसी की जाति पुष्टि न करे और न कोई किसी पर आड़े तरे। लोकतंत्र बहुमत से चलता है तानाशाही से नहीं। शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला बदलने में पूरे बीस साल का समय लिया। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जलजली का फैसला है। फैसला फेरकर फेरना है। इसे अब केवल देश की संसद नया कानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में आरक्षण अदालतों के फैसलों के खिलाफ अब कानून बनाना नहीं है। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वयंभू किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तर्क भी हैं। सभ्यता निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश

अम्बेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं लगा। वे कहते हैं कि अदालतों को अना-अजना के वर्गीकरण के अधिकार नहीं हैं। ये काम संसद ही कर सकती है। डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश विचित आवाजी पार्टी चलाते हैं। लेकिन वे आरक्षण विरोध नहीं हैं, ऐसा मे नहीं मानता। बाबा सरदार के पीठ होने का यह अर्थ मतलब भी संविधान विरोध होना नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से सोचते हैं। जिस दिन उजना बहुमत संसद में हो जाएगा, वे शीर्ष अदालत का फैसला बदलने या बदलवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिनाल तो शीर्ष अदालत के इस फैसले से कहीं खुशी,कहीं गम का माहौल है। ऐसा नहीं है। जैसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विषय में आये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हुआ है।

आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दल हो या दलों को राजनीति सीधेना वाले संघ, अपनी सुविधानुसार और बदलते आये हैं। जो आरक्षणसे कमी आरक्षण का प्रबल विरोध करता है वो ही सब आरक्षण का समर्थन करने लगता है। यही हाल सतत संघ भाजपा और अन्य दलों का है। इसीलिए सतत संघ से कम में तो शीर्ष अदालत के फैसले से कतुमर्द हैं। मैं जानता हूँ कि शीर्ष अदालत के इस तार्ना केसले के बाद भी राजनीतिक दल और नौकरशाही बीच का कोई रस्ता निकल कर अपना खूब सीधा चला है। अदालत ने अजना कानून किया है। आरक्षण की मलाई और छछ को लेकर ये द्वन्द भी हमारी ही समाज हो चुका है। जितनी राजनीति आरक्षण विरोधी और समर्थक बनती है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी।



फसल उत्पादन का मूल आधार पानी ही है परंतु आवश्यकता से अधिकता फसलों के लिए न केवल हानिकारक होती है, बल्कि भूमि की संरचना को बिगाड़ कर उसे फसल उपयुक्त ही नहीं रहने देती है। जल निकास वह विधि है जिसमें पौधों की उचित वृद्धि के लिए कृत्रिम ढंग से खेतों के अतिरिक्त पानी को भूमि की सतह अथवा अधोसतह से बाहर निकाला जाता है।

जल निकासी जरूरी

जल से हानियां

जल निकास के उचित प्रबंध के अभाव में खरीफ मौसम में मिट्टी के अंदर अत्यधिक नमी हो जाती है इस आवश्यकता से अधिक नमी के कारण वर्षाकालीन फसलों एवं मिट्टी को अनेकों हानियां होती हैं।

- भूमि में वायु संवार रुक जाता है।
- मिट्टी तब मिर जाती है।
- मिट्टी जीवाणुओं के कार्य में बाधा पड़ती है।
- पौधों की जड़ें उथली रह जाती हैं एवं सूख जाती हैं।
- भूमि की भौतिक दशा में परिवर्तन हो जाता है।
- पौधों के खाल पदार्थों में कमी आ जाती है।
- लवणों का मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमाव हो जाता है।
- जलवायु बुराई और कृषि क्रियाएं बहिन हो जाती हैं।
- बीजों का दर से जमाव एवं फसल की बढ़ाव रुक जाती है।
- रोग, कीट एवं खरपतवार का भयंकर आक्रमण होता है।

कहते हैं कि पानी सरीखा दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं। जहां मरणासन्न व्यक्ति में पानी प्राण ला देता है और जल जीवन का यह आधार है वही पानी की अधिकता कभी-कभी उसकी तबाही का कारण भी बन जाती है। पानी के संभ्रम में यही बात फसलों के साथ भी लागू होती है। फसल उत्पादन का मूल आधार पानी ही है परंतु आवश्यकता से

इसकी अधिकता फसलों के लिए न केवल हानिकारक होती है, बल्कि भूमि की संरचना को बिगाड़ कर उसे फसल उपयुक्त ही नहीं रहने देती है। जल निकास वह विधि है जिसमें पौधों की उचित वृद्धि के लिए कृत्रिम ढंग से खेतों के अतिरिक्त पानी को भूमि की सतह अथवा अधोसतह से बाहर निकाला जाता है।

जल निकास

हल्की मिट्टी की अपेक्षा भारी, चिकनी, चिकनी दोमट भूमियों में जल निकास की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि इनमें पानी का खराब अन्वेष नहीं होता है जिससे सतह पर पानी भरा रहता है। अतः जल निकास के लिए जल निकास नालियों का निर्माण करना पड़ता है। यह जल निकास नालियां अपनी आवश्यकतानुसार भूमि की ऊपरी सतह पर खुदी जाती अथवा भूमि के अंदर अथवा सतह पर नाली बनाई जाती है। जल निकास की दो विधियां अपनाई जाती हैं।

अधो पृथ्वीय जल निकास

जिन स्थानों पर जल स्तर ऊंचा उठ जाने के कारण भूमि के मूल क्षेत्र में पानी भरा रहता है वह भूमिगत जल निकास नालियां बनानी पड़ती हैं। यह जल निकास नालियां मुख्य रूप से कनारों के (दानों के) आधार पर लकड़ी, पत्थर, टाइल तीन प्रकार की होती हैं। मिट्टी की अपेक्षा सतह में 25-30 मीटर के आसानी अंतराल पर खेत के प्राकृतिक ढाल को देखते हुए समतल पर 1 मीटर की गहराई में 30 सेमी चौड़ी नाली बना देते हैं जिसे लकड़ी, पत्थर या टाइल से टाइल मिट्टी से ढाके देते हैं। इन नालियों में पानी के बहाव के लिए 30 मीटर की दर पर 5 सेमी का ढाल देते हुए बनाते हैं। इस प्रकार खेत की अधो सतह में सहायक नालियां बना देते हैं। जिन्हें सीधे उपयुक्त नालियों से तथा उपयुक्त नालियों को मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। जोड़ते समय ध्यान रखें कि नाली को कभी भी 90 अंश के कोण पर न जोड़ें। जल निकास में फलतु पानी प्रस्तावित होकर खेत से बाहर निकल जाता है। परिणामस्वरूप फसल पर नमी की अधिकता का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता और किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ प्राप्त हो जाता है।



पृथ्वीय जल निकासी

भारतीय कृषकों के लिए यह विधि अति सरल है। इसमें भूमि की ढाल, पानी की अधिकता आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता अनुसार दूरी पर खुदी हुई नाली खोद देते हैं जिन्हें होकर बरसात का पानी खेत से बाहर निकल जाता है। यह नाली खेत की सतह पर प्राकृतिक ढाल को देखते हुए खेत की सतह पर 30 सेमी गैरी बनाते हैं जिन्हें मेट्र 75 सेमी ऊंची रखते हैं। समय-समय पर इन नालियों की सफाई भी करते रहते हैं ताकि जल निकास में बाधा न पड़े।

मिट्टी जनिट रोगों तथा दीमक से सुरक्षा के लिए प्रति एकड़ 150 से 200 किग्रा नीम की पीसी हुई खल भी खेत की तैयारी के समय मिला दी जाती है। नर्सरी में इसकी पौध को कटिंग, बीज अथवा टिशू कल्चर से तैयार किया जाता है। कलम से तैयार पौधे अच्छे चलते हैं। स्टीविया का रोपण मेड़ों पर किया जाता है ये 1 से 1.5 फीट ऊंची व 2 फीट चौड़ी रखी जाती है।

औषधीय फसल

स्टीविया आमदनी बढ़ाये

जलवायु एवं मिट्टी

स्टीविया की फसल वर्षा को सहन कर लेती है उचित जल निकास आवश्यक है। मिट्टी रेतीली दोमट जिसका पीएच 6 से 7.5 के मध्य हो उपयुक्त रहती है।

भूमि की तैयारी तथा पौध रोपण -

स्टीविया की खेतों एक पंचवर्षीय फसल के रूप में की जाती है अतः खेत को जुलाई से तीन बार कर उसमें 3 टन केचुआ खाद अथवा 6 टन कम्पोस्ट खाद के साथ 120 किग्रा प्रीम जैविक खाद खेत में मिलावनी चाहिए। मिट्टी जनिट रोगों तथा दीमक से सुरक्षा के लिए प्रति एकड़ 150 से 200 किग्रा नीम की पीसी हुई खल भी खेत की तैयारी के समय मिला दी जाती है। नर्सरी में इसकी पौध को कटिंग, बीज अथवा टिशू कल्चर से तैयार किया जाता है। कलम से तैयार पौधे अच्छे चलते हैं। स्टीविया का रोपण मेड़ों पर किया जाता है ये 1 से 1.5 फीट ऊंची व 2 फीट चौड़ी रखी जाती है। पौधे से पौधे के मध्य 6 से 9 इंच व कतार से कतार 40 सेमी की दूरी रखते हैं। इस प्रकार एक एकड़ में 30 से 40 हजार पौधे लग जाते हैं। रोपण का उपयुक्त माह जुलाई-अगस्त व मार्च-अप्रैल है।

प्रजातियां

विश्व भर में स्टीविया की लगभग 90 प्रजातियां हैं। वर्तमान में स्थानीय जलवायु में एसआरबी-123 जिसकी वर्ष में 5 कटार्ड ली जा सकती है तथा एसआरबी-512 (चार कटार्ड) व एसआरबी 120 प्रमुख हैं।



सिंचाई

इसकी फसल को वर्ष भर निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचकाल के उपयोग के अलावा इसकी सिंचाई द्विप विधि से अधिक फायदेमंद है।

खरपतवार नियंत्रण एवं नियर्स-गुड़ाई

खरपतवार निकालने का कार्य हाथों से ही किया जाना चाहिए तथा इस हेतु रसायनिक खरपतवारनाशी काम में न लें।

पौधक तत्वों की आवश्यकता

फसल की निरंतर वृद्धि के लिए खाद के साथ-साथ प्रत्येक कटार्ड के बाद 500 किग्रा केचुआ खाद व 30 किग्रा प्रीम जैविक पौधों के पास डालना चाहिए। फसल में रसायनिक उर्वरकों एवं टांनिकों का प्रयोग न करें।

पौध संरक्षण

नियमित अंतरालों पर गोमूत्र अथवा नीम तेल का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फसल रोगों व कीटों से मुक्त रहती है।



कटार्ड व पतियों को सुखाना

रोपण के लगभग चार माह के उपरान्त भूमि से 15 से 20 सेमी की ऊंचाई तक फसल को कटार्ड करें। कटार्ड का कार्य पौधों पर फूल आने से पूर्व करें। आगे को कटार्ड प्रथम कटार्ड से 3-3 माह पर करते हैं। कटार्ड के बाद प्रायः 3 से 4 दिन तक पत्तों को छाया में सुखाया जाता है जिससे ये पूर्णतया नमी रहित हो जाते हैं।

उपज

खरपतवार फसल होने के कारण स्टीविया की उपज में प्रत्येक कटार्ड के साथ बढोत्तरी होती जाती है। चार कटार्डों से लगभग 2 से 4 टन पतियां प्रति हेक्टेयर उत्पादित होता है। औसतन फसल से वर्ष भर में लगभग 2.5 टन सूखे पत्तों प्राप्त होते हैं।

पैकिंग व शुद्ध लाभ

सूखी हुई पतियों को प्लास्टिक के बैगों में सील पैक कर भर दिया जाता है। इसकी खरीद देश की कई प्रमुख कंपनियों कर रही है तथा कई इसे पुनःखरीदी आधार पर प्रोत्साहित भी कर रही है। इसकी किंमत दर 80 से 120 रुपये प्रति किग्रा तक है। लागत को घटाकर अनुमान में मुनाफा करीब एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ बनता है। अच्छी तकनीक से उत्पाजनीय सूखी पतियों के पाउडर का मुख्य कृषक को दो सौ रुपये प्रति किलो तक मिल सकता है।

स्टीविया मूलतः

पेरू के का पौधा है परंतु इसकी खेती मुख्यतः कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रारंभ हो चुकी है। इसके पत्तों का स्वाद मीठा होता है, सूखी हुई पतियों में 3 से 20 प्रतिशत स्टीवियोसाइड होता है। यह मसुमेह रोगियों में डायबिटीस की मात्रा को घटाता है साथ ही रोगों के कैप्सूल की टाई, दंत मॉन बनाने व रक्त चाप कम करके उसे नियंत्रित करता है।



मिट्टी की सेहत सुधारने वाली

खाद

वर्मी कम्पोस्ट क्या है ?

बेकार कार्बनिक पदार्थों जैसे पशुओं का गोबर, कृषि अवशेष, खरपतवार के छिलके, घरेलू कचरा आदि जो आसानी से सड़-गल सकने वाले पदार्थ हैं जो केचुआ द्वारा भीजन के रूप में उपयोग किया है और जिसमें फलवस्त्र को पदार्थ निकलता है उसे वर्मी कम्पोस्ट (केचुआ खाद) कहते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि

- वर्मी कम्पोस्ट को छायादार किसी ऊंचे स्थान पर जहां पानी न भरता हो बेड तैयार करें।
- बेड की लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 4 फीट तथा गहराई 2 फीट हो। बेड को लकड़ी के मुरारी से पीटकर ढका व समतल बना लें।
- गड्डे की निचली सतह पर आसानी से अर्थात् होने वाले सूखी घास, पुआल, ज्वार के अंदल की छह इंच मोटी तह बना दें।
- इसके ऊपर छह इंच पकी हुई गोबर खाद डाल दें।
- केचुआ को डालने के बाद इसके ऊपर 9 इंच की मोटी परत लकड़ी के टुकड़े, झुलन, फीट आदि डालकर इसे मोटी तहपट्टी या जूट के बोरे से ढक दें।
- तहपट्टी पर प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार पानी छिड़कते रहें ताकि नमी 40 प्रतिशत बनी रहे।
- साह में एक बार खाद को ऊपर नीचे करके पलट दें।
- 30 दिन में छोट्टे-छोट्टे केचुआ दिखना शुरू हो जाते हैं इस अवस्था में बेड की सतह में चले जाते हैं।
- 50-60 दिन के बाद पानी छिड़कना बंद कर दें। जिससे कि केचुआ वर्मी बेड की सतह में चले जाते हैं।
- इस पद्धति से 50-60 दिन में खाद तैयार हो जाती है।
- इसके बाद गांधू से कम्पोस्ट निकालकर प्लास्टिक साँट पर ढेर लगा दें ताकि केचुआ खाद की निचली सतह में चले जाते हुए बाद में 2 मीट्री मोटी खाद वाली छतनी से खाद को छात लेंगे हैं।
- वर्मी हुई खाद को सुखा लें एवं बाँधियों में उपयोग के समय तक भंडारित कर रख सकते हैं।



पशुओं को कैसे बचाएं खुरपका मुंहपका से

यह रोग विषाणु से होने वाला अत्यंत संक्रामक रोग है। यह रोग फटे खुर वाले पशुओं में होता है। इस रोग को विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। खुसीरा, खुसू, खुसुवा, इत्यादि। सामान्यतः यह रोग गांव, भैंस, बकरी, भेड़ एवं सूकर पशुओं में होता है। इस रोग से काफी संख्या में छोटी उम्र के पशु मर सकते हैं। किंतु व्यस्क पशुओं में इस रोग के कारण मरु व 5 प्रतिशत अथवा इससे भी कम होती है। यह रोग बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है तथा कभी-कभी यह रोग पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकता है।

फैलने के कारण

- रोगी पशु की सार, दूधित सार, पानी, दूध गोबर एवं पेशाब से
- खाद एवं इत्रा के माध्यम से, एक से दूसरे पशु में। रोग से संक्रमित स्थान से पशु कूच करके लाने पर। रोगी पशु से सीधे सम्पर्क से
- इस रोग के विषाणु रोगी पशु के फेफड़ों से सूख जाने के बाद घास या चारागाह में गिर जाते हैं, जहाँ इन संक्रमित घास को स्वस्थ पशु खाता है, तो स्वस्थ पशु में यह रोग फैल जाता है।

लक्षण

- प्रारंभिक अवस्था में पशु सुस्त होता है। चारा खाना कम कर देता है।
- दूध देने वाले पशुओं का दूध कम हो जाता है। पशु को बहुत तेज बुखार आ जाता है। (106 फारेनहाइट तक)
- एक दो दिन के बाद मुँह तथा पिर में छाले पड़ जाते हैं।
- मुँह में छाले होने से लार टपकने लगती है।
- रोगी पशु लंगाने लगता है, कभी-कभी घाव में छाले में कीड़े पड़ जाते हैं।

उपचार- खुरपका

मुंहपका रोग एक विषाणु जनित रोग है। अतः इस रोग का कोई सीधा उपचार नहीं होता है। एक बार रोग हो जाने पर केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। इस रोग में रोगी पशु की प्रतिरक्षा बलता में कमी होने से पशु में अन्य रोगों के संक्रमण की संभावना हो सकती है। जिसके बचाव के लिए उपचार किया जाता है।

राज्य सरकार की निःशुल्क योजना से प्रेरित होकर जागरूक एवं समर्पित शिक्षक दानदाताओं के सहयोग से गरीब-मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं

सूत्र। अगर मन में सच्ची समाज सेवा, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की भावना हो तो समाज के अन्य दानी लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। इस बात को सच साबित कर दिखाया है गुजरात के संकल्प एजुकेशन ग्रुप ने, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों वाले इस ग्रुप के सदस्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिजिटल तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करके ज़रूरतमंद छात्रों और गरीबों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। समाज में आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के इरादे से सितंबर-2023 से व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई और एक छोटे से इरादे से शुरू किए गए इस ग्रुप से 10 महीने के अंदर 10 हजार सदस्य जुड़ गए हैं। 12 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक



मदद करना चाहता है, तो वे समूह में विवरण पोस्ट कर सकते हैं और व्यवस्थापक को दान राशि का ऑनलाइन शेषानक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन नेक उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करना इन शिक्षक मित्रों से सीधे होता है। विचारित्र को सूत्र जिले में लगाया था और एक साल के भीतर यह छोटाउदेंपुर, भरुच, नर्मदा, सूत्र, तापी,

सहायता प्रदान कर चुका है। आदिवासी उच्च शिक्षा चाहने वाले गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शि्षा काई योजना से जागरूक करने के साथ-साथ सरकारी एवं सहायक के समन्वय से आदिवासी क्षेत्र के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आमतौर पर व्हाट्सएप का उपयोग पाण्डुर, मंजेश्वर पोस्ट साइड कर, शैक्षणिक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन नेक उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करना इन शिक्षक मित्रों से सीधे होता है। विचारित्र को सूत्र जिले में लगाया था और एक साल के भीतर यह छोटाउदेंपुर, भरुच, नर्मदा, सूत्र, तापी,

नवसारी, वलसाड और खंडा तक बरगद के पूरे के रूप में फैल गया है। समूह सदस्यों के सहयोग से अब संकल्प एजुकेशन ग्रुप को 2,80,960 रुपये का फंड मिला गया है, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल फीस, वर्दी, जूते, किताबें, टेक्नोलॉजी, खेल किट जैसी विभिन्न वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे से शिक्षक और नवसारी जिले के मुद्दी के मूल निवासी मिनेशभाई पटेल, जो भरुच जिले के जुकेरिया में रहते हैं, इस समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि छात्रावासों या आश्रमशालाओं में रहने वाले, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे बिना फीस या शैक्षणिक सामग्री के अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें, इसके लिए उन्हें नेटवर्क, कैंपल, स्टडी किट दी जानी चाहिए,

जो यदि बच्चों के पास न तो नवनीत है और न ही गाइड, दो रूप के 10 हजार से ज्यादा सदस्य बच्चों के बीच सदैव, युनिफॉर्म, कपड़े जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का उद्धार नहीं हो सकता। नई पीढ़ी को शिक्षित करने से ही समाज तेजवृत्ति, सदस्य और प्रतिभावान बनेगा। अगर बच्चा पढ़ाई में होंशियर है लेकिन उसे फीस भरने में दिक्कत आती है तो हम जानकारी लेकर ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद करते हैं। उन जागरूकता के साथ-साथ छोटे-छोटे लोग भी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ऐसे सेवा कार्यों के लिए आगे आएंगे। पिछले 20 वर्षों में राज्य सरकार के आदिवासी उन्नयन के प्रयास अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जिसमें समाज सेवा

संस्थाओं का सहयोग भी सराहनीय है। मांडवी एकेडमी जनजातीय विकास जनजातीय उपयोगिता के तहत वनबंधु कल्याण योजना के तहत सूरजी जिले के नौ (9) तालुकाओं उमरपाड़ा, मांगरोल, बाराडोली, महुवा, परलना, कामरेज, आलपाड़ा, चौर्यासी में आदिवासी समुदायों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आदिवासी छात्रों को सरकारी स्कूलों, यू.वी. आश्रम स्कूलों, आश्रमशालाओं, छात्रावासों, आंगणवाड़ियों में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ शैक्षिक और भौतिक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जिले में विशेष रूप से चार एकलव्य मॉडल स्कूलों और एक सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। जिसमें कुल 1200 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। संकल्प एजुकेशन ग्रुप की सहायता

मेरी पढ़ाई और फीस भरने में बहुत उपयोगी साबित हुईं- लभार्थी प्रिंस वसावा, तालुका कच्छ, मांडवी। मांडवी तालुका के कच्छ गांव के मूल निवासी प्रकाशभाई वसावा के बेटे प्रिंस को पिछले साल खेड़ जिले के कामरसद में प्रमुखवाणी मैट्रिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला था। मिली मदद पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए प्रिंस वसावा ने कहा कि सहायता मिली वसावा, जो इस समूह के सदस्य और शिक्षक हैं, ने समूह से वित्तीय सहायता का अनुभव किया क्योंकि मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति खराब है। उस वक संकल्प ग्रुप ने मुझे 20 हजार रुपये की तत्काल सहायता दी. यह सहायता मेरी पढ़ाई और फीस भरने में बहुत उपयोगी साबित हुई।

टी एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में मनाया गया स्तनपान सप्ताह

सूत्र। दुनिया भर में स्तनपान को बढ़ावा देने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। फिर टी एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सूत्र को और से स्तनपान सप्ताह मनाया गया। अश्वकताराम ट्रस्ट के संस्थापक एमल मचेंद्र ग्रेस्ट फौंडेशन चोक समग्रहा के आरंभकर्ता के रूप में उद्घटित रहे। कार्यक्रम में स्तनपान पर एक प्रस्ताव चर्चा हुई, जिसमें छात्रों ने इसके महत्व और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

और बच्चे के बीच सभ्य रिश्ते की शुरुआत है। स्तनपान शिशु और माँ दोनों के लिए जीवनदायी है। यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। स्तन के दूध में एंटीबॉडी, पोषक तत्व, विकास कारक और एंटीबायोटिक्स होते हैं जो शिशुओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस अवसर पर गुजरात नर्सिंग काउंसिल की आई.ए. इकबाल कडविला ने विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर को कम करने में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के बाद नवजात के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। यह स्तनपान की सुरक्षा, प्रचार और समर्थन के लिए डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ

की वार्षिक पहल का फोकस है। माँ का दूध नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, स्तनपान न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि माँ के लिए भी ज़रूरी है। टी एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रोफेसर किरण डोमडिया ने स्तनपान और माँ के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में नर्सिंग छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि नवजात शिशुओं और माताओं की देखभाल में दाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। माँ का दूध बच्चों को संरक्षण, दस्त और जल्दी से बचता है।

महिला एवं बाल अधिकारी कार्यालय द्वारा कतारगाम के अक्षर ज्योति हाई स्कूल में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' उत्सव मनाया गया

सूत्र। महिला एवं बाल अधिकारी कार्यालय की ओर से 2 अगस्त को शहर के कतारगाम स्थित अक्षर ज्योति हाई स्कूल में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' 2024 के तहत छेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ दिवस मनाया गया। जिसमें 6वीं से 11वीं कक्षा तक के लगभग 250 विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराध, लैंगिक समता, महिला उन्मुख योजना और महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न बगनों के बारे में जानकारी दी गई। रिमताबेन देसाई ने कार्यक्रम में उद्घोषित बच्चों एवं अभिभावकों को लैंगिक समता के बारे में समझाते हुए कहा कि समाज को सुधराने के लिए महिलाएं एवं तृतीय लिंग के बारे में गलत-सहीफैमियों से बचना चाहिए। विद्व. संसार, संसार, पण्डितजी ने कोई महिला नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए गर्भ में पल

रहे बच्चे के लिंग का परीक्षण नहीं है। माँ, बेटी, पति आदि नारी संबंधों से ही संसार कायम है। केवल एक प्राणी ही दूसरे प्राणी को जन्म दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में लिंग आधारित सेक्स स्थापना है। रिमता देसाई ने आगे कहा कि महिला हेल्थलाइन, सखी वन स्टॉप सेंटर, 181 अभयम, महिला स्वावलंबन योजना, विधवा सहाय योजना, विधवा पुर्निक्रम सहाय योजना, वली छोटी योजना, महिला संरक्षण गृह, पीबीएससी सेंटर स्पेस महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी दी. पहल एवं बहुआयामी योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास कचहरी के महेशभाई पणमर पर संकेत करें। ने बच्चों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के साइबर

अपराध जैसे निवेश धोखाधड़ी, क्यूरेट ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग पर धोखा, प ड 1, गुप्तित के नाम पर धोखाधड़ी, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और सोशल मीडिया के उपयोग, विधवा पुर्निक्रम सहाय योजना, वली छोटी योजना, महिला संरक्षण गृह, पीबीएससी सेंटर स्पेस महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी दी. पहल एवं बहुआयामी योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास कचहरी के महेशभाई पणमर पर संकेत करें। ने बच्चों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के साइबर

अपराध जैसे निवेश धोखाधड़ी, क्यूरेट ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग पर धोखा, प ड 1, गुप्तित के नाम पर धोखाधड़ी, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और सोशल मीडिया के उपयोग, विधवा पुर्निक्रम सहाय योजना, वली छोटी योजना, महिला संरक्षण गृह, पीबीएससी सेंटर स्पेस महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी दी. पहल एवं बहुआयामी योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास कचहरी के महेशभाई पणमर पर संकेत करें। ने बच्चों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के साइबर

अपराध जैसे निवेश धोखाधड़ी, क्यूरेट ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग पर धोखा, प ड 1, गुप्तित के नाम पर धोखाधड़ी, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें और सोशल मीडिया के उपयोग, विधवा पुर्निक्रम सहाय योजना, वली छोटी योजना, महिला संरक्षण गृह, पीबीएससी सेंटर स्पेस महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी दी. पहल एवं बहुआयामी योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास कचहरी के महेशभाई पणमर पर संकेत करें। ने बच्चों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के साइबर

मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल ने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ खून से संबंधित सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक, थ्रोम्बोसिटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा (TTP) से पीड़ित 61 वर्षीय महिला का सफलतापूर्वक इलाज किया



लोगों में से किसी एक को अपनी चोट में लीता है। मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजी विभाग के सैनियर केमस्ट्री डॉ. कौमिल पटेल इस मरीज का इलाज करने वाली टीम की कमान संभाल रहे थे। TTP, यानी थ्रोम्बोसिटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा से संबंधित एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें पूरे शरीर में छोटे ब्लाड वेल्स में खून के थक्के बनते लगते हैं। इन थक्कों के कारण ब्लेडेटेड की संख्या में कमी (थ्रोम्बोसाइटोपेनिया) हो सकती है, रेड ब्लाड सेल्स गट (हेमोलिटिक एरिथ्रिया) हो सकते हैं और सीमित मात्रा में खून के बहन की वजह से शरीर के अंगों को की मिसाल कायम की है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा (TTP) को एक आपात स्थिति माना जाता है, तथा इससे जुड़ी गंभीर जटिलताओं या मौत को रोकने के लिए तुरंत इलाज

करना बेहद जरूरी हो जाता है। प्लास्मा एक्सचेंज थेरेपी (प्लास्माफेरेसिस) में इसका प्राथमिक उपचार है, जिसमें बीमारी के लिए जिम्मेदार एंटीबॉडीज को शरीर से बाहर निकालकर उन्हें स्वस्थ प्लास्मा से बदल दिया जाता है। 61 साल की सोनिया देवी इस बीमारी से पीड़ित थीं, जिन्हें हेमोलोलायन और प्लेटलेट के गंभीर रूप से कम स्तर के साथ मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल के आपातकालीन सेवा विभाग में लाया गया था। जब उन्हें डॉक्टरों के पास लाया गया, तो उसमें गंभीर रूप से कमजोरी, लंबा पर नोले निशान और कई अंगों में खराबी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। शुरुआती जाँच और चिकित्सकीय कोशल से जल्दी ही पता चल गया कि वह TTP से पीड़ित थीं। TTP की वजह से मरीज अस्पताल में भर्ती होने समय कई तरह की जटिलताओं का सामना कर रही थीं, जिसका असर उनके फेफड़ों, किडनी, हार्ट और त्रेन पर भी पड़ गया।

उनका इलाज करने वाले हेमेटोलॉजिस्ट, डॉ. कौमिल पटेल और समर्पित आईसीयू टीम ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बीमारी से जुड़ी हर जटिलता का विशेषज्ञ तरह से इलाज किया जाए। उनकी हालत को स्थिर करने और अधिक विगानुने से रोकने के लिए उपचार के विभिन्न क्षेत्र के चिकित्सा विशेषज्ञों का सहयोग बेहद जरूरी था। प्लास्मा एक्सचेंज थेरेपी के खून से प्लास्मा निकाला जाता है और उन्हें स्वस्थ प्लास्मा से बदल दिया जाता है। उनकी सेहत में सुधार लाने में पंचमनीलोगी, नेफ्रोलॉजी, कार्डिओलॉजी और यूरोलॉजी सहित विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों द्वारा सहायता मिली। प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टीएम से पीड़ित मरीजों का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें उन्हें इलाज के लिए 55 दिनों तक लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। इस अवधि के दौरान, मरीज को कई बार प्लास्मा एक्सचेंज सेशन, गहन निगरानी तथा विशेष अंगों की जटिलताओं के लिए उपचार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें पीड़ित मरीजों को ठीक होने में चिकित्सकों को टीम के लगातार कोशिश और मरीज की शारीरिक क्षमता सबसे ज्यादा माथने की रहती है। अस्पताल से छुट्टी मिलते समय मरीज की सेहत काफी अच्छी होती है, और इस मरीज को मामले में भी ऐसा ही था। अस्पताल से छुट्टी मिलते समय उनके हेमोलोलायन और प्लेटलेट का स्तर स्थिर था, साथ ही अंगों में खराबी के कोई लक्षण नहीं थे। उनकी स्वस्थ उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुई, जो मैरिंगो सीआईएमएस हॉस्पिटल में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तथा अस्पताल द्वारा बड़े पैमाने पर मरीजों को भलाई के लिए अपनाये गए तरीकों की मिसाल है। डॉ. कौमिल पटेल, सैनियर केमस्ट्री,

हेमेटोलॉजी विभाग, ने कहा, "थ्रोम्बोसिटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का इलाज करना चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ बेहतर परिणाम देने वाला भी है। इस बीमारी में बड़े पैमाने पर माइक्रोवैस्कुलर क्लॉटिंग होती है, और अगर इलाज न हो तो इलाज नहीं किया जाए तो यह तेजी से जानलेवा बन सकती है। हम प्लास्मा एक्सचेंज थेरेपी को मदद से इसका प्राथमिक उपचार करते हैं। यह इलाज की एक महत्वपूर्ण विधि है, जो तथा मृत्यु दर को काफी हद तक कम करने के साथ-साथ लंबे समय के परिणामों में सुधार कर सकती है। इसमें बीमारी पैदा करने वाले एंटीबॉडीज को शरीर से बाहर निकालकर उन्हें स्वस्थ प्लास्मा से बदल दिया जाता है, जो प्लेटलेट्स और रेड ब्लाड सेल्स को तट होने से रोकने में मदद करता है। हालाँकि इसके उपचार की प्रक्रिया काफी गहन है और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन तुरंत रह स्वस्थ

होने की संभावना इसे और भी अधिक आवश्यक बना देती है। ज़रूरतसे पीड़ित किसी मरीज को ठीक होने हुए देखना, सही मायने में हेमेटोलॉजी में सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक है। डॉ. कौमिल पटेल ने TTP जैसी खून से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में शुरुआत में इसकी पहचान के साथ-साथ तुरंत उपचार शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "इसके लक्षणों का संदेह होने पर जल्द से-जल्द इसकी पहचान करना और बिना देरी के तुरंत इलाज शुरू करना, मरीज के लिए परिणामों को बेहतर बनाने में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का साथ मिलकर काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर जब एकजुट होकर कोशिश करते हैं, तो इस तरह के मामलों की जटिलताओं को सफलता के साथ-साथ के लिए सबसे बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलती है।"

लोड़ा की सार्वजनिक सूचना: रितेश खोसला को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का जनरल काउंसिल नियुक्त किया गया है

लोड़ा को अनोखी और गोमा में नियोजित विकास और/या होटलों के निर्माण के बारे में पृष्ठछाड़ मिल रही है। घर खरीदारों और हितधारकों के बीच स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, डेवलपर ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लोड़ा का उल्लिखित कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है। कृपया ध्यान रखें कि लोड़ा भारत का नं. 1 एक रियल एस्टेट डेवलपर * है, जो मुंबई (एमएमआर), पुणे और बैंगलोर में काम कर रहा है। इसकी अनोखी या गोमा में कोई परियोजना नहीं है। लोड़ा का हाउस ऑफ ऑनर्स लोड़ा (HoA) या मित्रो-जुलते लोड़ा या लोड़ा का उपयोग करने वाला किसी अन्य कंपनी से कोई संबंध नहीं है। संभावित घर खरीदारों और हितधारकों को लोड़ा

परियोजनाओं की पहचान करने में मदद करने के लिए, बेहतर स्पष्टता और विश्वसनीयता के लिए लोड़ा की आधिकारिक वेबसाइट www.lodha-group.com पर जाने को सिफारिश की जाती है।

मुंबई। कॉर्पोरेट प्रशासन, जटिल मुकदमेबाजी और बौद्धिक संपदा अधिका, सुरक्षा और प्रवर्तन शामिल हैं। अपनी नियुक्ति पर विचार करते हुए, रितेश खोसला ने कहा: "सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में जनरल काउंसिल बनने पर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मेरी यात्रा अवधिस्थानीय रूप से समृद्ध रही है, और मैं हमारी प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। यह भूमिका एक नई चुनौती करती है।" एक मजबूत कानूनी नींव बनाने का अहसास। मैं कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और अंतर-दशकों को असाधारण सामग्री और अनुभव प्रदान करने के सोनी पिक्चर्स, उनकी विशेषज्ञता में विश्वास और अधिग्रहण, नेटवर्क्स इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ, नियामक ढाँचे, अपाएलन, के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

अपनी नई भूमिका में, रितेश सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के कॉर्पोरेट संबंध, कानूनी और नियामक मामलों, संचिनीय और मानक और अभ्यास कार्यों की देखरेख करेंगे। वह जोड़िए और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, अपनी कानूनी जोड़ियों का प्रबंधन करेंगे और कंपनी के लोकपाल के रूप में काम करेंगे। वह सीधे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीओओ को रिपोर्ट करेंगे। अपने मुख्य कर्तव्यों के अलावा, रितेश सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के अनुपालन ढाँचे को बढ़ाने की पहल का नेतृत्व करेंगे, विशेष रूप से डिजिटल और बौद्धिक संपदा अधिकारों में। वह अंतर-दशकों बाजारों में कंपनी के कानूनी ढाँचे को भी मजबूत करेंगे और एएसपीएमआई की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (एसएसआर) पहल का प्रणय है।

रितेश खोसला ने कहा: "सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में जनरल काउंसिल बनने पर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मेरी यात्रा अवधिस्थानीय रूप से समृद्ध रही है, और मैं हमारी प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। यह भूमिका एक नई चुनौती करती है।" एक मजबूत कानूनी नींव बनाने का अहसास। मैं कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और अंतर-दशकों को असाधारण सामग्री और अनुभव प्रदान करने के सोनी पिक्चर्स, उनकी विशेषज्ञता में विश्वास और अधिग्रहण, नेटवर्क्स इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ, नियामक ढाँचे, अपाएलन, के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

अपनी नई भूमिका में, रितेश सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के कॉर्पोरेट संबंध, कानूनी और नियामक मामलों, संचिनीय और मानक और अभ्यास कार्यों की देखरेख करेंगे। वह जोड़िए और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, अपनी कानूनी जोड़ियों का प्रबंधन करेंगे और कंपनी के लोकपाल के रूप में काम करेंगे। वह सीधे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीओओ को रिपोर्ट करेंगे। अपने मुख्य कर्तव्यों के अलावा, रितेश सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के अनुपालन ढाँचे को बढ़ाने की पहल का नेतृत्व करेंगे, विशेष रूप से डिजिटल और बौद्धिक संपदा अधिकारों में। वह अंतर-दशकों बाजारों में कंपनी के कानूनी ढाँचे को भी मजबूत करेंगे और एएसपीएमआई की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (एसएसआर) पहल का प्रणय है।

रितेश खोसला ने कहा: "सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया में जनरल काउंसिल बनने पर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मेरी यात्रा अवधिस्थानीय रूप से समृद्ध रही है, और मैं हमारी प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। यह भूमिका एक नई चुनौती करती है।" एक मजबूत कानूनी नींव बनाने का अहसास। मैं कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और अंतर-दशकों को असाधारण सामग्री और अनुभव प्रदान करने के सोनी पिक्चर्स, उनकी विशेषज्ञता में विश्वास और अधिग्रहण, नेटवर्क्स इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ, नियामक ढाँचे, अपाएलन, के लिए प्रतिबद्ध हूँ।